1	2	3	4
8	Orissa	124-60	47-08
9	Punjab	2,042-76	7-03
10.	Rajasthan	27,629-78	754-76
11	Uttar Pradesh	58,048-10	6,154-72
12	West Bengal	5,007-00	46-14
13	Pondicherry	260-49	19-08
14	Delhi	343-15	1-99
15	Chandigarh	13-63	—
16	Cantonment Areas	606-18	21-79
	TOTAL	2,18,356-29	14,190-66

राजनीतिक दलों की तरफ बकाया किराया

3536. राधाकिशन मालवीय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी इमारतों का उपयोग किए जाने पर उनकी तरफ किराये की बहुत सी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल की तरफ बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के लिए सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली (एम०आर०टी०एस०)

3537. श्री आनन्द प्रकाश गौतम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दिल्ली के लिए "सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली" (एम०आर०टी०एस०) योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस प्रणाली के अधीन नोएडा तथा गाजियाबाद जो कि दिल्ली के समीप हैं; जैसे आधुनिक औद्योगिक शहरों को शामिल किए जाने का कोई प्रावधान है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) मैसर्स रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि० द्वारा किए गए प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता अध्ययन में निम्नलिखित यातायात कोरिडोरों पर जनद्रुतगामी परिवहन प्रणाली आरम्भ करने की सिफारिश की गई है :—

1. विश्वविद्यालय–आई०एस० बी०टी० – कनाट प्लेस–केन्द्रीय सचिवालय–इसे बसंतकुंज तक बढ़ाया जा सकता है।

2. तिलक ब्रिज–पटेल नगर–नजफगढ़।

3. तिलक ब्रिज–शाहदरा–आई एस बीटी–रामपरा–नांगलोई।

4. सब्जीमंडी–होलम्बी कलां–नरेला ।

5. तिलक ब्रिज–ओखला–तुगलकाबाद ।

6. दयाबस्ती–पालम–बिजवासन ।

7. निजामुद्दीन–पटेल नगर–रोहिणी–बरवाला ।

उपर्युक्त प्रणाली का निर्माण क्रमिक रूप में किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसे कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 20 वर्षों में चालू किया जा सकेगा । इस परियोजना में लगभग 7500 करोड़ रुपए का (1992-93 की कीमतों के आधार पर) निवेश होगा । इस परियोजना के लिए बजट स्रोतों से धनराशि उपलब्ध कराना सरकार के लिए संभव नहीं है । अतः परियोजना के निष्पियन के लिए वैकल्पिक स्रोत जुटाने होंगे । होने वाले निवेश को देखते हुए परियोजना के प्रारंभ/पूरा होने की समय-सारणी का उल्लेख करना जल्दबाजी होगी ।

(ख) दिल्ली में एम०आर०टी०एस० की योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना शामिल है । तथापि नोएडा तथा गाजियाबाद जैसी शहरी बस्तियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली महानगर क्षेत्र में आने वाले अन्य क्षेत्रों को जोड़ना संभव है । इस समय मैसर्स रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि० द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद हेतु एक पृथक् परिवहन अध्ययन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ यातायात की मांगों और अन्य भूमिगत वास्तविकताओं के आधार पर इन शहरों को दिल्ली एम०आर०टी०एस० के साथ जोड़ने संबंधी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।

Setting up of Desalination Plants In Rural Areas

3538. SHRI GHUFRAN AZAM :
SHRI KRISHNA KUMAR BURLA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government has commissioned desalination plants in rural areas to provide safe drinking water in the country

(b) if so, the details of such desalination plants set up in rural areas *ot* the country as on 31st December, 1993 ;

(c) whether Government' propose set up more desalination plants in the coantry ; and

(d) if so, by when the target to achieve the goal of safe drinking water is likely to be achieved ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT "SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) The State-wise details of desalination plants set up under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission[1] (RGNDWM) are as under:

Andhra Pradesh	11
Gujarat	11
Haryana	2
Maharashtra	2
Poudicherry	3
Rajasthan	86
Tamil Nadu	20
West Bengal	1
Lakshadweep	11
TOTAL	147

Apart from the above, 3 plants in Andhra Pradesh, 2 plants in Rajasthan and 2 plants in West Bengal have been installed but not, yet commissioned.

(c) and (d) Under the Sub Mission on Control of Brackishness in Drinking Water schemes are taken up through alternative safe sources or if this is not cost effective/ feasible, desalination plants are provided. The setting up of more such plants during the Eighth Plan period will depend upon the specific proposals from the States wherever alternative safe sources are not available.